



अगस्त 2026

योजना

पत्रिका का
सारांश



नागरिक सशक्तीकरण

विषय 1: भारत के मुक्त व्यापार समझौते: आर्थिक कूटनीति का एक नया युग (INDIA'S FREE TRADE AGREEMENTS: A NEW ERA OF ECONOMIC DIPLOMACY)

मुक्त व्यापार समझौते (FTAs), सक्रिय व्यापार समझौते (13), भारत-मॉरीशस CECPA, भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA, भारत-यूएई CEPA, भारत-ओमान CEPA, भारत-ब्रिटेन CETA, भारत-EFTA TEPA, भारत-न्यूजीलैंड FTA, और भारत-यूरोपीय संघ FTA (लेखक: हर्ष वर्धन श्रृंगला, राज्यसभा सांसद एवं पूर्व विदेश सचिव)

आर्थिक कूटनीति विजन: “2025 को भारत की आर्थिक कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। 2025 के अंत तक, भारत के पास 13 सक्रिय मुक्त व्यापार समझौते हैं। साथ ही, सरकार आज की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपनी निवेश संधियों की समीक्षा कर रही है।” — हर्ष वर्धन श्रृंगला

1. कार्यकारी सारांश एवं आर्थिक कूटनीति का नया स्वरूप

अगस्त 2026 के ‘योजना’ अंक (विषय: नागरिक सशक्तीकरण) के पहले आलेख ‘भारत के मुक्त व्यापार समझौते: आर्थिक कूटनीति का एक नया युग’ में राज्यसभा सांसद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने विश्लेषण किया है कि कैसे 2025 और 2026 की शुरुआत में भारत ने वैश्विक साझेदारों के साथ अपने व्यापार समझौतों को सक्रिय रूप से अपडेट और अंतिम रूप दिया है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया भर के प्रमुख साझेदारों के साथ नौ प्रमुख व्यापार समझौतों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। प्रारंभिक 2026 तक भारत के पास 13 सक्रिय मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) हैं। सरकार आज की वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने, निवेशक सुरक्षा और राष्ट्रीय नीति प्राथमिकताओं को संतुलित करने के लिए अपनी निवेश संधियों और अधिमन्य व्यापार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रही है।

2. प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) और रणनीतिक साझेदारियां

- भारत-मॉरीशस CECPA (फरवरी 2021):** किसी अफ्रीकी राष्ट्र के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता, जो वित्तीय प्रवाह से आगे बढ़कर वस्तुओं, सेवाओं और निवेश सुविधा में सहयोग को बढ़ावा देता है। इससे

तमिलनाडु, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र के परिधान निर्यातकों को रियायती बाजार पहुंच मिलती है।

- भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (दिसंबर 2022):** क्वाड फ्रेमवर्क के तहत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय साझेदारों के साथ आर्थिक जुड़ाव और आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम।
- भारत-यूएई CEPA (मई 2022):** मध्य पूर्व में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और ऊर्जा आपूर्तिकर्ता, जो खाड़ी, अफ्रीका और यूरोप में भारतीय व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।
- भारत-ओमान CEPA (दिसंबर 2025):** पश्चिमी हिंद-प्रशांत में रणनीतिक स्थिति और ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने वाला समझौता।
- भारत-ब्रिटेन CETA (जुलाई 2025):** ब्रेक्सिट के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था के साथ एक व्यापक समझौता, जो आईटी, स्वास्थ्य सेवा और कंसल्टेंसी जैसे क्षेत्रों में भारतीय पेशवरों की आवाजाही को सुगम बनाता है।
- भारत-EFTA TEPA (अक्टूबर 2025):** स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लीचेंस्टीन के साथ इस समझौते के तहत EFTA ने 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का वादा किया है।
- भारत-न्यूजीलैंड FTA (दिसंबर 2025):** कृषि और डेयरी संवेदनशीलता को संतुलित करते हुए प्रशांत क्षेत्र के साथ कैलिब्रेटेड जुड़ाव।
- भारत-यूरोपीय संघ (EU) FTA (दिसंबर 2025):** जिसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा गया है, यह यूरोपीय संघ को भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनाता है (भारत के माल व्यापार का 11.5%)।

3. भारत की व्यापार नीति में रणनीतिक बदलाव

भारत की व्यापार नीति अब केवल बाजार पहुंच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन और सेवाओं को एकीकृत करने वाले व्यापक समझौतों की ओर बढ़ रही है। विकसित भारत @2047 के विजन की ओर बढ़ते हुए, ये समझौते निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे, गुणवत्तापूर्ण निवेश आकर्षित करेंगे और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) के साथ भारत के एकीकरण को गहरा करेंगे।

4. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: प्रमुख व्यापार समझौते, हस्ताक्षर वर्ष और रणनीतिक फोकस

नीचे दी गई तालिका भारत के प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs), उनके कार्यान्वयन और रणनीतिक उद्देश्यों का विवरण प्रस्तुत करती है:

व्यापार समझौता (FTA)	हस्ताक्षर / प्रभावी वर्ष	मुख्य भौगोलिक क्षेत्र / भागीदार	रणनीतिक उद्देश्य व लाभ
भारत-मॉरीशस CECPA	फरवरी 2021 (प्रभावी अप्रैल 2021)	अफ्रीकी महाद्वीप (मॉरीशस)	दक्षिण-दक्षिण सहयोग और परिधान/वस्त्र निर्यात का विविधीकरण
भारत-यूएई और ओमान CEPA	यूएई (मई 2022); ओमान (दिसंबर 2025)	खाड़ी क्षेत्र (Middle East / West Asia)	ऊर्जा सुरक्षा, निवेश सुविधा और खाड़ी/अफ्रीका में प्रवेश द्वार
भारत-ब्रिटेन CETA	जुलाई 2025	यूनाइटेड किंगडम (यूरोप)	पेशवरों (IT, स्वास्थ्य सेवा) की आवाजाही और MSME आपूर्ति श्रृंखला
भारत-EFTA TEPA	मार्च 2024 (प्रभावी अक्टूबर 2025)	EFTA ब्लॉक (स्विस, नॉर्वे, आदि)	15 वर्षों में 100 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्राप्त करना
भारत-EU FTA	दिसंबर 2025 ('मदर ऑफ ऑल डील्स')	यूरोपीय संघ (EU)	वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन और अभूतपूर्व बाजार पहुंच

5. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख अंतरराष्ट्रीय संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था और आर्थिक कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (अंतरराष्ट्रीय संबंध, द्विपक्षीय समझौते, वैश्विक समूह और भारतीय अर्थव्यवस्था — निर्यात व निवेश)

- **भारत की आर्थिक कूटनीति और FTAs:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारत अपने 13 सक्रिय मुक्त व्यापार समझौतों (जैसे यूएई, ब्रिटेन, EFTA, EU) के माध्यम से पारंपरिक बाजार पहुंच से आगे बढ़कर निवेश-लिंकड बाजार पहुंच (जैसे EFTA का \$100B निवेश वादा) और भू-आर्थिक लचीलापन हासिल कर रहा है।
- **विकसित भारत @2047 और वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVCs):** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन के बीच भारत को एक विश्वसनीय आर्थिक साझेदार के रूप में स्थापित करने में व्यापार समझौतों की भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा आर्थिक कूटनीति दृष्टिकोण: “भारत के व्यापार समझौतों का बढ़ता नेटवर्क एक अधिक रणनीतिक, विविध और दूरदेशी व्यापार नीति की ओर स्पष्ट बदलाव को दर्शाता है। विकसित भारत @2047 के विजन की ओर बढ़ते हुए, ये समझौते निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करेंगे।” — हर्ष वर्धन श्रृंगला

विषय 2: साझेदारी से प्रगति की ओर: सहकारी संघवाद क्रियान्वयन में (FROM PARTNERSHIP TO PROGRESS: COOPERATIVE FEDERALISM IN ACTION)

सहकारी संघवाद, NITI Aayog गवर्निंग काउंसिल (11वीं बैठक 2026), स्टेट सपोर्ट मिशन (SSM), स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन (SITs) जैसे MITRA, GRIT), आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम (ADP & ABP), NITI for States पोर्टल, और विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम (VBSR) (लेखक: के.एस. रेजीमोन, संयुक्त सचिव, NITI Aayog एवं अन्य)

सहकारी संघवाद विजन: “एक विकसित भारत और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा किसी एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है; यह एक साझा राष्ट्रीय प्रयास है। सहकारी संघवाद विश्वास, सहयोग और साझा जिम्मेदारी पर आधारित है।” — के.एस. रेजीमोन, शोजाहमेद कलाल एवं डॉ. अमृत पाल कौर

1. कार्यकारी सारांश एवं सहकारी संघवाद का महत्व

अगस्त 2026 के «योजना» अंक (विषय: नागरिक सशक्तीकरण) के तीसरे आलेख «साझेदारी से प्रगति की ओर: सहकारी संघवाद क्रियान्वयन में» (From Partnership to Progress: Cooperative Federalism in Action) में नीति आयोग के स्टेट सपोर्ट मिशन के संयुक्त सचिव और मिशन डायरेक्टर के.एस. रेजीमोन, डायरेक्टर शोजाहमेद कलाल और पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट डॉ. अमृत पाल कौर ने विश्लेषण किया है कि कैसे भारत का संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों को समान भागीदारों के रूप में जोड़ता है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए केवल केंद्र सरकार का प्रयास पर्याप्त नहीं है; राष्ट्रीय प्रगति सभी राज्यों की

सामूहिक प्रगति पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण कि «जब राज्य बढ़ते हैं, तो भारत बढ़ता है» के साथ, सहकारी संघवाद संवैधानिक सिद्धांत से बढ़कर शासन की एक ऐसी पद्धति बन गया है जहां राष्ट्रीय दृष्टिकोण और स्थानीय समाधान मिलकर काम करते हैं।

2. परामर्श से सह-सृजन (Co-Creation) तक की यात्रा

- **संस्थागत मंच:** नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल (जिसकी 11वीं बैठक 2026 में हुई) और मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत संवाद, नीति सह-सृजन और कार्यान्वयन-केंद्रित रणनीति के लिए शीर्ष मंच के रूप में कार्य करते हैं।
- **सह-सृजन मॉडल:** केंद्र-राज्य संबंध अब सीमित वित्तीय हस्तांतरण या एकतरफा निर्देशों से आगे बढ़कर सतत संवाद, ज्ञान साझा करने और संयुक्त समस्या-समाधान (co-creation) की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं।

3. दीर्घकालिक विकास के लिए मजबूत संस्थाएं (State Support Mission)

- **स्टेट सपोर्ट मिशन (SSM):** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए नीति आयोग राज्यों में ‘स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन’ (SITs) की स्थापना का समर्थन करता है।
- **राज्य-स्तरीय मॉडल:** महाराष्ट्र में MITRA, त्रिपुरा में TIFT, और गुजरात में GRIT जैसी संस्थाएं नीति आयोग की तर्ज पर दीर्घकालिक सुधारों को गति दे रही हैं। राजस्थान और आंध्र प्रदेश ने भी विजन 2047 के तहत SITs को आगे बढ़ाया है।
- **अकादमिक साझेदारी:** आईआईएम कलकत्ता (त्रिपुरा की फार्मास्युटिकल नीति हेतु) और आईआईटी रुड़की (उत्तराखंड के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली) जैसी प्रमुख संस्थाएं साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण में सहयोग कर रही हैं।

4. जमीनी स्तर पर सहकारी संघवाद: ADP और ABP

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP):** 2018 में शुरू किया गया यह कार्यक्रम 28 राज्यों के 112 सबसे पिछड़े जिलों (16% आबादी) के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को गति देता है। यह ‘तीन C’—अभिसरण (Convergence), सहयोग (Collaboration), और प्रतियोगिता (Competition)—पर आधारित है, तथा इसका फोकस ‘व्यय मापने’ से हटकर ‘परिणाम मापने’ (Outcomes) पर है।
- **आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP):** ADP की सफलता पर आधारित यह कार्यक्रम 331 जिलों के 513 ब्लॉकों में अति-स्थानीय (hyper-local) चुनौतियों का समाधान करता है।
- **स्थानीयकरण:** सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को स्थानीय प्राथमिकताओं में अनुवादित कर राज्य और स्थानीय सरकारें प्रगति को ट्रैक कर रही हैं।

5. डेटा-संचालित शासन (Data-Driven Governance) और डिजिटल उपकरण

- **NITI for States पोर्टल:** 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध यह राष्ट्रीय ज्ञान भंडार नीति दस्तावेजों, सर्वोत्तम प्रथाओं और डेटासेट को समेकित करता है, जिसमें AI Sarthi उपयोगकर्ताओं को डेटा नेविगेट करने में मदद करता है।

- **विकसित भारत स्ट्रेटेजी रूम (VBSR):** एकीकृत डैशबोर्ड और वास्तविक समय के विश्लेषण के माध्यम से अंतरिक्ष-आधारित विजुअलाइजेशन और अंतर-विभागीय समन्वय को सुगम बनाता है।
- **NITITARA और क्षेत्र विकास रणनीति (ADS):** जिला और ब्लॉक प्रशासन के लिए हाल ही में लॉन्च किया गया 'अनुभव-में-बक्सा' (experience-in-box) टूल Kulgam (J&K) और Kondagaon

(Chhattisgarh) जैसे जिलों में साक्ष्य-आधारित योजना को मजबूत कर रहा है।

6. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: सहकारी संघवाद के आयाम, मंच और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका सहकारी संघवाद के प्रमुख संस्थानों, कार्यक्रमों, डिजिटल पहलों और उनके विकासात्मक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

संघवाद आयाम	मुख्य मंच / पहल	परिचालन पैमाना व फोकस	विकासात्मक प्रभाव
उच्च-स्तरीय नीति मंच	नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल और मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन	केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत संवाद और सह-सृजन	समान साझेदारों के रूप में राष्ट्रीय एजेंडा तय करना
संस्थागत सुदृढीकरण (SSM)	स्टेट सपोर्ट मिशन और SITs (जैसे MITRA, TIFT, GRIT)	राज्य स्तर पर दीर्घकालिक विजन 2047 और नीति अनुसंधान संस्थान	राज्यों की योजना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण क्षमता में वृद्धि
जमीनी बदलाव (ADP & ABP)	आकांक्षी जिला कार्यक्रम (112 जिले) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (513 ब्लॉक)	16% आबादी को कवर करना और अति-स्थानीय चुनौतियों का समाधान	व्यय से हटकर परिणामों (Outcomes) पर आधारित शासन और स्वस्थ प्रतियोगिता
डेटा-संचालित शासन	NITI for States पोर्टल, AI Sarthi, VBSR और NITITARA	800+ जिलों और ब्लॉकों में एकीकृत डैशबोर्ड और डिजिटल उपकरण	प्रतिक्रियाशील प्रशासन से हटकर दूरदर्शी और साक्ष्य-आधारित निर्णय

7. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख भारतीय राजनीति, संघवाद, शासन व्यवस्था और नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II (भारतीय संविधान की विशेषताएं — संघवाद के आयाम, केंद्र-राज्य संबंध, और नीति आयोग की भूमिका)

- **सहकारी संघवाद से सह-सृजन (Co-Creation):** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारत का संघीय ढांचा वित्तीय हस्तांतरण से आगे बढ़कर नीति निर्माण में सह-सृजन और संस्थागत सहयोग (जैसे SITs और State Support Mission) की ओर बढ़ रहा है।
- **जमीनी स्तर पर सुशासन (ADP & ABP):** आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रमों के माध्यम से 'प्रतिस्पर्धा और अभिसरण' (Competition and Convergence) के मॉडल को प्रदर्शित करता है, जो व्यय के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है।

मुख्य परीक्षा सहकारी संघवाद दृष्टिकोण: "सहकारी संघवाद विश्वास, सहयोग और साझा जिम्मेदारी पर आधारित है, जहां केंद्र, राज्य, जिले और स्थानीय संस्थान चुनौतियों का समाधान करने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं।" — के.एस. रेजीमोन, शोजाहमेद कलाल एवं डॉ. अमृत पाल कौर

विषय 3: स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (HTA): भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का एक रणनीतिक उपकरण (HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT: A STRATEGIC TOOL FOR ACHIEVING UNIVERSAL HEALTH COVERAGE IN INDIA)

स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (HTA), HTAIn (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग), सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC), मूल्य निर्धारण और खरीद निर्णय (राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन, C-Tb परीक्षण), स्वास्थ्य लाभ पैकेज (Health Benefit Packages) का युक्तिकरण, और क्षमता निर्माण (लेखक: डॉ. राजीव बहल, सचिव, DHR एवं महानिदेशक, ICMR)

स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन विजन: "जैसे-जैसे भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर बढ़ रहा है, चुनौती केवल अधिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की नहीं होगी, बल्कि ऐसी बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की होगी जो न्यायसंगत, किफायती और संघारणीय हो। HTA इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है।" — डॉ. राजीव बहल

1. कार्यकारी सारांश एवं HTA की आवश्यकता

अगस्त 2026 के 'योजना' अंक के पांचवें आलेख 'स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन: भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का एक रणनीतिक उपकरण' (Health Technology Assessment: A Strategic Tool for Achieving Universal Health Coverage in India) में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने विश्लेषण किया है कि कैसे स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (HTA) भारत में UHC के लक्ष्य को हासिल करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोगों को वित्तीय कठिनाई के बिना गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। भारत जैसे विशाल और विविध देश में इसके लिए केवल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सावधानीपूर्वक चुनाव करने की मांग करता है कि कौन सी स्वास्थ्य तकनीकों, दवाओं, निदान उपकरणों और हस्तक्षेपों को अपनाया जाए। HTA नैदानिक प्रभावशीलता, लागत-प्रभावशीलता (cost-effectiveness), सुरक्षा, समानता और नैतिक विचारों के आधार पर स्वास्थ्य तकनीकों का व्यवस्थित मूल्यांकन करता है।

2. HTAIn की स्थापना और राष्ट्रीय भूमिका

- **HTAIn का गठन:** राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के बाद स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) के तहत 'हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन इंडिया' (HTAIn) की स्थापना की गई थी।
- **कार्य और अध्ययन:** तकनीकी साझेदारों, संसाधन केंद्रों और उपयोगकर्ता विभागों के नेटवर्क के माध्यम से HTAIn ने 176 पूर्ण अध्ययन और 103 चल रहे अध्ययन पूरे किए हैं, जो नीति, खरीद, मूल्य निर्धारण और कार्यक्रम कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं।

- **लागत और मूल्य निर्धारण:** सिकल सेल एनीमिया मिशन के तहत रैपिड पॉइंट-ऑफ-केयर परीक्षणों के लिए HTA मूल्यांकन ने लागत को भारी रूप से कम किया और हजारों करोड़ रुपये की बचत की संभावनाओं को जन्म दिया।

3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और वित्तपोषण में योगदान

- **राष्ट्रीय क्षय रोग (TB) उन्मूलन कार्यक्रम:** C-Tb परीक्षण और डिजिटल अनुपालन निगरानी उपकरणों (digital adherence tools) के मूल्यांकन ने लागत को कम किया और TB कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बचत की।
- **स्वास्थ्य लाभ पैकेज (Health Benefit Packages):** सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सैकड़ों स्वास्थ्य लाभ पैकेजों के संशोधन और युक्तिकरण (rationalisation) में HTAIn ने सहायता की है। उदाहरण के लिए, स्तन कैंसर के लिए ट्रास्टुजुमाब (trastuzumab) थेरेपी के छह महीने के कोर्स ने लागत-प्रभावी विकल्प प्रदान किया।
- **राज्य-स्तरीय कार्यक्रम:** पूर्वोत्तर राज्यों में शिशु बेरीबेरी को रोकने के लिए थियामिन अनुपूरक (thiamine supplementation) कार्यक्रम और

ओडिशा के DAMAN (मलेरिया उन्मूलन) कार्यक्रम को HTA साक्ष्यों के आधार पर समर्थन मिला।

4. आत्मनिर्भर भारत और क्षमता निर्माण

- **स्वदेशी नवाचार:** घरेलू स्तर पर विकसित डायग्नोस्टिक्स, चिकित्सा उपकरणों और डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करके HTA 'आत्मनिर्भर भारत' विजन का समर्थन करता है।
- **क्षमता निर्माण (Capacity Building):** देश भर में HTA पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 6 विश्वविद्यालयों में M.Sc. HETA पाठ्यक्रम, iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर पॉलिसी निर्माताओं के लिए बुनियादी HTA पाठ्यक्रम, फैलोशिप, और क्षेत्रीय संसाधन केंद्र (22 क्षेत्रीय संसाधन केंद्र और 8 संसाधन हब) स्थापित किए गए हैं।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: HTA के आयाम, अनुप्रयोग और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका HTA के मुख्य घटकों, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इसके अनुप्रयोग और विकासात्मक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

HTA आयाम	मुख्य फोकस व कार्य	परिचालन पैमाना व नेटवर्क	सार्वजनिक स्वास्थ्य व वित्तीय प्रभाव
HTAIn संस्थागत ढांचा	स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों की नैदानिक और लागत-प्रभावशीलता का व्यवस्थित मूल्यांकन	176 पूर्ण अध्ययन, 103 चल रहे अध्ययन, 22 क्षेत्रीय संसाधन केंद्र.	साक्ष्यों के आधार पर स्वास्थ्य निर्णय लेना, अनुमानों के आधार पर नहीं
खरीद और मूल्य निर्धारण	सिकल सेल एनीमिया मिशन और TB कार्यक्रम के लिए लागत अनुकूलन	सिकल सेल और Ccdrynj-Tb परीक्षण लागत में भारी कमी.	सार्वजनिक संसाधनों की हजारों करोड़ रुपये की बचत.
स्वास्थ्य लाभ पैकेज	सरकारी बीमा योजनाओं के तहत लाभ पैकेजों का युक्तिकरण.	स्तन कैंसर और अन्य उपचारों के लिए लागत-प्रभावी थेरेपी [cite: 84, 85]	राज्यों और बीमा योजनाओं में वित्तीय स्थिरता और न्यायसंगत पहुंच
क्षमता निर्माण व नवाचार	M.Sc. HETA पाठ्यक्रम, iGOT कर्मयोगी कोर्स और स्वदेशी नवाचार समर्थन.	8 संसाधन हब, 10 तकनीकी साझेदार और 5 ADOPT केंद्र.	भविष्य के लिए कुशल नीति निर्माताओं और मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण.

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और स्वास्थ्य नीति के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II (स्वास्थ्य, मानव संसाधन और सामाजिक क्षेत्र के विकास से संबंधित मुद्दे — UHC और प्राथमिकता निर्धारण)

- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) और HTA:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे HTAIn (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के तहत) सीमित सार्वजनिक संसाधनों का सबसे प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए UHC के लक्ष्यों (किफायती, सुलभ और न्यायसंगत देखभाल) को प्राप्त करने में मदद करता है।
- **साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना:** स्वास्थ्य वित्तपोषण, खरीद रणनीतियों (जैसे सिकल सेल एनीमिया और TB परीक्षण) और स्वास्थ्य लाभ पैकेजों के युक्तिकरण में आर्थिक साक्ष्यों की भूमिका को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन दृष्टिकोण: “स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन (HTA) यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य सेवा पर खर्च किया गया प्रत्येक रुपया अधिकतम संभव स्वास्थ्य प्रभाव पैदा करे। यह 2047 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में भारत की यात्रा का एक कोने का पत्थर है।” — डॉ. राजीव बहल

विषय 4: भारत की कल्याणकारी वितरण वास्तुकला का विकास और प्रभाव (EVOLUTION AND IMPACT OF INDIA'S WELFARE DELIVERY ARCHITECTURE)

JAM ट्रिनिटी (जन धन, मोबाइल, डिजिटल पहचान), प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS), ऐतिहासिक वित्तीय बचत (₹3.5-4 लाख करोड़), और भविष्य के चार डिजिटल सुधार स्तंभ (लेखक: सौरभ के. तिवारी, अपर सचिव, DBT मिशन, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं अंशुमान कमिला)

कल्याणकारी वितरण विजन: “एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, भारत नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक vulnerabilities से बचाने के लिए बाध्य है। इस दायित्व की प्रभावशीलता नीति निर्माण स्तर पर नहीं बल्कि अंतिम छोर पर वितरण स्तर पर स्थापित होती है।” — सौरभ के. तिवारी एवं अंशुमान कमिला

1. कार्यकारी सारांश एवं पारंपरिक मध्यस्थता की समाप्ति

अगस्त 2026 के 'योजना' अंक (विषय: नागरिक सशक्तीकरण) के प्रमुख आलेख 'भारत की कल्याणकारी वितरण वास्तुकला का विकास और प्रभाव' (Evolution and Impact of India's Welfare Delivery Architecture) में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मिशन (मंत्रिमंडल सचिवालय) के अपर सचिव सौरभ के. तिवारी और उप निदेशक अंशुमान कमिला ने विश्लेषण किया है कि कैसे JAM ट्रिनिटी ने भारत में कल्याणकारी वितरण प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में कल्याणकारी लाभों के वितरण के लिए स्थानीय कार्यालयों, वितरण एजेंटों और संवितरण अधिकारियों के माध्यम से «स्तरित मध्यस्थता» (layered intermediation) पर भरोसा किया जाता था, जिसमें देरी, विवेक और विचलन (diversion) आम समस्याएं थीं। इस अंतर को पाटने और राजकोष तथा नागरिक के बीच सीधा संबंध स्थापित करने के लिए JAM ट्रिनिटी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) की अवधारणा को लागू किया गया।

2. तीन स्तंभों का ढांचा: JAM ट्रिनिटी

- **जन धन योजना (PMJDY):** वित्तीय बुनियादी ढांचा स्थापित करते हुए अगस्त 2014 से अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिससे औपचारिक बैंकिंग पहुंच से वंचित नागरिकों (विशेषकर महिलाओं) को जोड़ा गया है।
- **डिजिटल पहचान:** एक अनूठी राष्ट्रीय डी-डुप्लीकेट रजिस्ट्री के रूप में पहचान सुनिश्चित करना, जिससे यह प्रामाणिक आश्वासन मिलता है कि दावाकर्ता एक वास्तविक, जीवित और अनूठा व्यक्ति है।
- **मोबाइल कनेक्टिविटी:** उच्च टेली-डेंसिटी (94.02%) और किफायती टैरिफ के माध्यम से OTP सत्यापन, सेवा सूचनाएं और स्मार्टफोन्स के जरिए बायोमेट्रिक/चेहरे की पहचान को संभव बनाना।

3. संस्थागत विकास और मापनीय प्रभाव (Measurable Impact)

- मंत्रिमंडल सचिवालय में DBT मिशन: केंद्रीय योजनाओं (50 से अधिक मंत्रालयों/विभागों की 300+ योजनाएं) और राज्य की 2,500+ योजनाओं के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय सुनिश्चित करना।
- ऐतिहासिक बचत: 2014 से 2026 की अवधि के आकलन के अनुसार, 10 करोड़ से अधिक डुप्लीकेट, फर्जी और गैर-मौजूद लाभार्थियों को हटाने से लगभग ₹3.5–4 लाख करोड़ की संचयी बचत हुई है। इसमें खाद्य सब्सिडी सुधारों का हिस्सा ₹3.13 लाख करोड़ है।

वितरण आयाम	मुख्य वास्तुकला / पहल	परिचालन पैमाना व आंकड़े	सुशासन और राजकोषीय प्रभाव
JAM ट्रिनिटी बुनियादी ढांचा	जन धन खाते, डिजिटल पहचान और मोबाइल कनेक्टिविटी.	58 करोड़+ जन धन खाते और 94.02% टेली-डेंसिटी.	पारंपरिक मध्यस्थता और बिचौलियों को समाप्त करना. जोड़ों को सीधा वित्तीय लाभ।
राजकोषीय अनुशासन (PFMS)	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT).	300+ केंद्रीय योजनाएं और 2,500+ राज्य योजनाएं समर्थित.	कोष से अंतिम लाभार्थी तक धन की पूरी ट्रेसिबिलिटी और पारदर्शिता.
मापनीय वित्तीय प्रभाव	डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों को हटाना व प्रत्यक्ष डीबीटी.	10 करोड़+ फर्जी नाम हटे; ₹3.5–4 लाख करोड़ की संचयी बचत.	राजकोषीय घाटे में कमी और पारदर्शी तरीके से ₹40+ लाख करोड़ का वितरण.
भविष्य के 4 सुधार स्तंभ	सक्रिय सामाजिक रजिस्ट्रियां, जीवन-चक्रीय सिंक और e-Rupee.	मैनुअल आवेदनों से हटकर स्वतः वितरण (Proactive delivery).	शून्य समावेशन/बहिष्करण त्रुटियां और उद्देश्य-बद्ध 'स्मार्ट' कल्याण.

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख कल्याणकारी वितरण, ई-गवर्नेंस और सुशासन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है: सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग, और सरकारी योजनाओं का वितरण)

- **JAM ट्रिनिटी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT):** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे जन धन, मोबाइल और डिजिटल पहचान के अभिसरण ने बिचौलियों और लीकेज को समाप्त कर ₹3.5–4 लाख करोड़ की ऐतिहासिक बचत की है।

- **व्यापक कवरेज:** इस अवधि में लाभार्थी कवरेज 11 करोड़ से बढ़कर 180+ करोड़ हो गई, तथा कुल संचयी DBT हस्तांतरण ₹40+ लाख करोड़ तक पहुंच गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन राहत सीधे नागरिकों के खातों में पहुंचाई गई।

4. भविष्य के सुधार के चार स्तंभ (4 Pillars of Future Digital Reform)

भविष्य की डिजिटल वास्तुकला को मैनुअल अनुप्रयोगों से proactive वितरण की ओर ले जाने के लिए चार प्रमुख सुधार प्रस्तावित किए गए हैं :

1. **हर नागरिक के लिए एक विशिष्ट पहचान (One Identity):** बंटी हुई प्रणालियों को समाप्त करने के लिए पहचान को एकमात्र विशिष्ट आईडी के रूप में अनिवार्य करना.
2. **सक्रिय लाभार्थी पहचान (Proactive Identification):** नागरिकों से व्यक्तिगत आवेदन मांगने के बजाय सामाजिक रजिस्ट्रियों (Social Registries) के माध्यम से सरकार द्वारा स्वतः पात्र नागरिकों तक पहुंचना.
3. **जन्म से मृत्यु तक जीवन-चक्रीय समन्वय (Cradle-to-Grave Sync):** जन्म पंजीकरण, स्कूल नामांकन और कल्याणकारी पालता को एक सतत डिजिटल रिकॉर्ड में जोड़ना.
4. **उद्देश्य-बद्ध 'स्मार्ट' कल्याण (Purpose-Bound Welfare):** केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (e-Rupee) का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना कि छात्रवृत्ति या कृषि ऋण जैसे आवंटन केवल उनके निर्धारित उद्देश्य के लिए ही खर्च किए जाएं.

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: कल्याणकारी वितरण वास्तुकला, पैमाना और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका भारत की कल्याणकारी वितरण वास्तुकला के प्रमुख घटकों, पैमाने और सुधारों का विवरण प्रस्तुत करती है:

- **सुशासन और सक्रिय वितरण (Proactive Delivery):** मैनुअल आवेदनों से हटकर सामाजिक रजिस्ट्रियों, जीवन-चक्रीय समन्वय और e-Rupee (CBDC) जैसी भविष्य की सुधार रणनीतियों के माध्यम से नागरिक सशक्तीकरण को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा कल्याणकारी वितरण दृष्टिकोण: “प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), JAM ट्रिनिटी द्वारा संचालित, सार्वजनिक कल्याण वितरण को अधिक कुशल, प्रभावी और समावेशी बनाने में परिवर्तनकारी रहा है... यह नागरिकों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ और कुशल एवं जवाबदेह शासन दोनों को जन्म देता है।” — सौरभ के. तिवारी एवं अंशुमान कमिला

विषय 5: स्टार्टअप और नवाचार क्रांति: एक दशक जिसने भारत के आर्थिक डीएनए को बदल दिया (THE STARTUP AND INNOVATION REVOLUTION: A DECADE THAT CHANGED INDIA'S ECONOMIC DNA)

स्टार्टअप इंडिया पहल (2016), DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स (2.26 लाख+), प्रत्यक्ष नौकरियां (23.36 लाख), महिलाओं की भागीदारी (48%), टियर-2 और टियर-3 शहरों में विस्तार (52%+), फंड ऑफ फंड्स और TEJAS पहल (लेखक: अतीश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव, DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

स्टार्टअप क्रांति विजन: “पहली बार, भारत सरकार ने औपचारिक और विशेष रूप से कहा कि वह उद्यमिता को समर्थन के योग्य एक पेशे के रूप में मान्यता देती है। भारत को जितने नौकरी चाहने वालों की जरूरत है, उतनी ही नौकरी पैदा करने वालों की भी जरूरत है।” — अतीश कुमार सिंह

1. कार्यकारी सारांश एवं स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत

अगस्त 2026 के 'योजना' अंक के नौवें आलेख 'स्टार्टअप और नवाचार क्रांति: एक दशक जिसने भारत के आर्थिक डीएनए को बदल दिया' (The Startup and Innovation Revolution: A Decade That Changed India's Economic DNA) में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के DPIIT के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह ने विश्लेषण किया है कि कैसे पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत के आर्थिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि 16 जनवरी 2016 को जब स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की गई थी, तब देश में 400 से कम मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे और अधिकांश युवा सरकारी नौकरियों या पारंपरिक निगमों की ओर उन्मुख थे। सरकार ने पहली बार उद्यमिता को औपचारिक मान्यता दी और 19-सूचीय एक्शन प्लान (जिसमें फंड ऑफ फंड्स, कर छूट और सरलीकृत पेटेंट जांच शामिल थी) के जरिए एक मजबूत संस्थागत आधार तैयार किया।

2. प्रमुख आंकड़े और विकास (Scale and Achievements)

- DPIIT-मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स:** आज भारत में 56 उद्योगों और 700 से अधिक जिलों में 2.26 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं। अकेले FY 2025-26 में 55,200 नए स्टार्टअप्स को मान्यता मिली (51.6% की वार्षिक वृद्धि)।

स्टार्टअप आयाम	मुख्य फोकस व नीतिगत उपकरण	परिचालन पैमाना व आंकड़े	आर्थिक व सामाजिक प्रभाव
पारिस्थितिकी तंत्र का पैमाना	DPIIT मान्यता, 19-सूचीय एक्शन प्लान और संस्थागत मान्यता	2.26 लाख+ मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स, 700+ जिलों में उपस्थिति	नौकरी चाहने वालों को नौकरी देने वालों (Job Creators) में बदलना
रोजगार और महिला नेतृत्व	समावेशी उद्यमिता और महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को प्रोत्साहन	23.36 लाख+ प्रत्यक्ष नौकरियां; 48% स्टार्टअप्स में महिला निदेशक/पार्टनर	आर्थिक विकास में लैंगिक बाधाओं को तोड़ना और समावेशिता बढ़ाना
वित्तीय सहायता (FFS)	फंड ऑफ फंड्स, एंजेल टैक्स की समाप्ति और सीड फंड योजना	FFS के तहत ₹7,000+ करोड़ प्रतिबद्धता, ₹26,900+ करोड़ कुल निवेश	शुरुआती और विकास चरणों में पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना
भौगोलिक और वैश्विक विस्तार	TEJAS जिला आउटरीच और स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (SRF)	52%+ स्टार्टअप्स टियर-2/3 शहरों से; 120+ यूनिर्कोर्न (\$350B+ मूल्य)	महानगरों से बाहर स्टार्टअप संस्कृति का विकेंद्रीकरण और वैश्विक नेतृत्व

- रोजगार सृजन:** इन स्टार्टअप्स ने 23.36 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित की हैं, जिसमें पिछले एक साल में 36.1% की वृद्धि हुई है।
- महिला नेतृत्व:** सभी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में से लगभग 48% (1.10 लाख से अधिक) में कम से कम एक महिला निदेशक या पार्टनर हैं, जो महिला उद्यमियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।
- टियर-2 और टियर-3 शहरों का विस्तार:** 52% से अधिक स्टार्टअप अब महानगरों से बाहर (जयपुर, कोयंबटूर, भुवनेश्वर, इंदौर, लखनऊ, सूरत आदि) से संचालित हो रहे हैं, और देश के सभी 700+ जिलों में कम से कम एक पंजीकृत स्टार्टअप है।

3. वित्तीय बुनियादी ढांचा और सहायता तंत्र

- फंड ऑफ फंड्स (FFS):** अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIFs) के माध्यम से स्टार्टअप के लिए ₹7,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धता, जिससे ₹26,900 करोड़ से अधिक का निवेश जुटाया गया है। नया फंड ऑफ फंड्स 2.0 (₹10,000 करोड़ कॉर्पस) विशेष रूप से डीप-टेक, विनिर्माण और टियर-2/3 शहरों पर केंद्रित है।
- एंजेल टैक्स की समाप्ति:** 2024 में एंजेल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, जिससे शुरुआती चरण के निवेश में अनिश्चितता दूर हुई।
- TEJAS और जिला-स्तरीय पहुंच:** TEJAS (Transforming Entrepreneurial Journeys Across State & Districts) पहल के माध्यम से 130 से अधिक जिलों में कार्यशालाओं और आउटरीच कार्यक्रमों के द्वारा जमीनी स्तर पर युवाओं और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है।

4. वैश्विक स्थिति और भविष्य की प्राथमिकताएं (Deep Tech & Innovation)

- वैश्विक रैंकिंग:** भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें 6.6 लाख से अधिक उद्यम और 120 से अधिक यूनिर्कोर्न शामिल हैं जिनका कुल मूल्यांकन 350 अरब डॉलर से अधिक है।
- भावी चुनौतियां (Deep Tech):** अगले दशक की प्राथमिकताओं में केवल प्रक्रिया अनुकूलन नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, जल सुरक्षा, खाद्य उत्पादन और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में नई विज्ञान और मौलिक खोज (invention) शामिल होनी चाहिए।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: स्टार्टअप इंडिया के आयाम, आंकड़े और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका स्टार्टअप इंडिया के मुख्य संकेतकों, वित्तीय उपकरणों और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख स्टार्टअप, उद्यमिता, आर्थिक सुधारों और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है: सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (भारतीय अर्थव्यवस्था — उद्यमिता, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र, रोजगार सृजन, नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकार)

- स्टार्टअप इंडिया और आर्थिक डीएनए: यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे पिछले एक दशक में स्टार्टअप इंडिया पहल (2.26 लाख+ स्टार्टअप, 23.36 लाख नौकरियां) ने भारत के पारंपरिक रोजगार ढांचे को बदलकर युवाओं को 'नौकरी चाहने वाले' से 'नियोक्ता' (Job Creators) में परिवर्तित किया है।
- विकेंद्रीकरण और समावेशी नवाचार: टियर-2 और टियर-3 शहरों (52%+ स्टार्टअप) तथा महिला उद्यमियों (48%) की बढ़ती भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने और समावेशी आर्थिक विकास के मॉडल को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा स्टार्टअप क्रांति दृष्टिकोण: “पहली बार, भारत सरकार ने औपचारिक और विशेष रूप से कहा कि वह उद्यमिता को समर्थन के योग्य एक पेशे के रूप में मान्यता देती है। भारत को जितने नौकरी चाहने वालों की जरूरत है, उतनी ही नौकरी पैदा करने वालों की भी जरूरत है।” — अतीश कुमार सिंह

विषय 6: DAY-NRLM: बढ़ती आकांक्षाओं को पंख देना (DAY-NRLM: GIVING WINGS TO SOARING ASPIRATIONS)

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), महिला स्व-सहायता समूह (SHG) लामबंदी, लखपति दीदी लक्ष्य (3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़), डिजिटल अभिसरण प्लेटफॉर्म LokOS, महिला उद्यम त्वरण कोष (WEAF), SHE मार्ट्स, समावेशी आजीविका योजना (SAY), और 'नयी चेतना 4.0' अभियान (लेखक: चरणजीत सिंह, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव एवं आरती पंचल)

आजीविका मिशन विजन: “प्रधानमंत्री के सेवा तीर्थ कार्यालय में स्थानांतरित होने पर उनके द्वारा हस्ताक्षरित पहली फाइलों में से एक लखपति दीदियों के लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने का निर्णय था। आज DAY-NRLM दुनिया के सबसे बड़े सामुदायिक-संचालित और महिला-नेतृत्व वाले विकास कार्यक्रमों में से एक है।” — चरणजीत सिंह एवं आरती पंचल

1. कार्यकारी सारांश एवं DAY-NRLM का विशाल पैमाना

अगस्त 2026 के 'योजना' अंक के दूसरे आलेख 'DAY-NRLM: बढ़ती आकांक्षाओं को पंख देना' में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पूर्व अतिरिक्त सचिव चरणजीत सिंह और DAY-NRLM की कंसलटेंट आरती पंचल ने विश्लेषण किया है कि कैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने ग्रामीण गरीबों को संगठित करने और वित्तीय समावेशन में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा लखपति दीदी के लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ (अगले 3 वर्षों में प्राप्त करने हेतु) करना इस कार्यक्रम के प्रति सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में लगभग 10.03 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 94 लाख स्व-सहायता समूहों (SHGs) में संगठित किया गया है। अब तक ₹64,405 करोड़ से अधिक की पूंजीकरण सहायता प्रदान की गई है, जिसके मुकाबले बैंकों से ₹12 लाख करोड़ से अधिक का ऋण लिया गया है, और इसका एनपीए (NPA) remarkably कम यानी मात्र 1.85% है।

2. डिजिटल शासन: LokOS प्लेटफॉर्म और डेटा डिजिटलीकरण

- LokOS का महत्व:** कार्यक्रम के तहत व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) की कमी को दूर करने के लिए 'LokOS' (Lok = People, OS = Operating System) प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर rollout किया गया है, जो सामुदायिक संस्थानों के भीतर डिजिटल शासन को मजबूत करता है।
- ई-बुक कीपर्स की भूमिका:** इस विशाल डेटा डिजिटलीकरण और मानकीकरण अभियान में 4 लाख से अधिक सामुदायिक कैडरों (e-Book Keepers) को SHG और संघ-स्तरीय रिकॉर्ड को LokOS प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट करने के लिए तैनात किया गया।
- अंतर-राज्यीय सहयोगात्मक तंत्र:** आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (SRLMs) ने राष्ट्रीय संसाधन संगठनों (NROs) के रूप में अन्य राज्यों को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और मार्गदर्शन प्रदान किया।

3. व्यक्तिगत उद्यम, महिला बैंक और विपणन (SHE Marts)

- महिला उद्यम त्वरण कोष (WEAF):** SHG सदस्यों को बड़े ऋण और व्यक्तिगत उद्यमों को अपस्केल करने में मदद करने के लिए WEAF लॉन्च किया गया है, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ 'स्वयं सिद्धा' जैसे ऋण उत्पाद शुरू किए गए हैं।
- ब्रांडिंग और e-Saras:** झारखंड का 'पलास' (और उसकी आदिवासी आभूषण उप-ब्रांड 'आदिवा') जैसे ब्रांड्स के साथ-साथ e-Saras पोर्टल ऑनलाइन विपणन को बढ़ावा दे रहा है।
- SHE (Self-Help Entrepreneur) Marts:** केंद्रीय बजट में घोषित SHE मार्ट्स को SHG महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए समर्पित खुदरा और एकत्रीकरण स्थानों के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिससे बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।

4. अंतिम छोर तक पहुंच (Samaveshi Aajeevika Yojana) और लैंगिक समानता

- समावेशी आजीविका योजना (SAY):** विश्व बैंक की रिपोर्ट (2025) के अनुसार अत्यधिक ग्रामीण गरीबी में तेज गिरावट आई है, लेकिन जो परिवार SHG की पंचसूत्र शर्तों (जैसे नियमित बचत) को पूरा नहीं कर पाते, उन्हें जोड़ने के लिए SAY उप-योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1,50,000 से अधिक सबसे हाशिए के परिवारों को कवर किया गया है।
- 'नयी चेतना 4.0' अभियान:** महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए 25 नवंबर से 23 दिसंबर के बीच 'नयी चेतना 4.0' अभियान एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के रूप में चलाया गया, जिसमें 12 केंद्रीय मंत्रालयों और 39 लाख से अधिक गतिविधियों के माध्यम से 14 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: DAY-NRLM के आयाम, हस्तक्षेप और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका DAY-NRLM के मुख्य आयामों, डिजिटल पहलों, उद्यम संवर्धन और सामाजिक समावेशन का विवरण प्रस्तुत करती है:

NRLM आयाम	मुख्य फोकस व लक्ष्य	परिचालन पैमाना व उपलब्धियां	सामाजिक-आर्थिक प्रभाव
महिला लामबंदी (Mobilisation)	ग्रामीण महिलाओं को SHG में संगठित करना और लक्ष्य दीदी लक्ष्य (6 करोड़)	10.03 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 94 लाख SHGs में संगठित	सामूहिक शक्ति और वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण
डिजिटल शासन (LokOS)	सामुदायिक संस्थानों का डिजिटलीकरण और MIS सुदृढीकरण	34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और 762 जिलों में LokOS का प्रसार	पारदर्शी डेटा प्रबंधन और नीति नियोजन में सुधार
विपणन (SHE Marts & e-Saras)	SHG उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और खुदरा केंद्र	e-Saras पोर्टल और जिला स्तर पर SHE Marts की स्थापना	बिचौलियों को हटाकर सीधे बाजार तक पहुंच और बेहतर ब्रांडिंग
अंतिम छोर तक पहुंच (SAY)	अत्यंत गरीब और छूटे हुए परिवारों को SHG दायरे में लाना	समावेशी आजीविका योजना (SAY) के तहत 1.5 लाख अवशेष कवर	सबसे हाशिए के वर्गों को गरीबी के जाल से बाहर निकालना

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख ग्रामीण विकास, महिला सशक्तीकरण और आजीविका मिशन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र (गरीबी, विकास प्रक्रिया, महिला स्व-सहायता समूह और ग्रामीण आजीविका योजनाएं)

- DAY-NRLM और महिला-नेतृत्व विकास:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे SHG आंदोलन (10 करोड़+ महिलाएं) और लक्ष्य दीदी का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को केवल कल्याणकारी लाभार्थियों से निकालकर आर्थिक रूप से समृद्ध और स्वतंत्र उद्यमी बना रहा है।
- डिजिटल शासन और विपणन चुनौतियां:** LokOS प्लेटफॉर्म, SHE Marts और समावेशी आजीविका योजना (SAY) के माध्यम से डिजिटल शासन, विपणन अंतराल और अंतिम छोर तक समावेशन की प्रशासनिक सफलताओं को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा आजीविका मिशन दृष्टिकोण: “DAY-NRLM को गरीबी उन्मूलन के अपने उन्मुखीकरण से आगे बढ़कर महिलाओं को सशक्त, समृद्ध बनाने तथा उनके साथ मजबूत सामुदायिक संगठन बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। यह परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि ग्रामीण महिलाएं भारत की विकास गाथा में समान हितधारक बनें।” — चरणजीत सिंह एवं आरती पंचल

विषय 7: PM-SETU: युवाओं का सशक्तीकरण और भारत को कौशल राजधानी बनाना (PM-SETU: EMPOWERING YOUTH, POSITIONING INDIA AS SKILL CAPITAL)

PM-SETU योजना, 1,000 सरकारी ITI का आधुनिकीकरण (200 हब और 800 स्पोक ITI), ₹60,000 करोड़ का वित्तीय परिव्यय, 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCE), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शिक्षा और कौशल का एकीकरण, और विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) मॉडल (लेखक: दिलीप कुमार, महानिदेशक (प्रशिक्षण), DGT, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय)

कौशल विकास दृष्टि: “जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ध्यान ऐसे संस्थानों के निर्माण पर रहा है जो कुशल, उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित हों। PM-SETU इस विकसित शासन दृष्टिकोण को दर्शाता है।” — दिलीप कुमार

1. कार्यकारी सारांश एवं कौशल विकास का महत्व

अगस्त 2026 के ‘योजना’ अंक के चौथे आलेख ‘PM-SETU: युवाओं का सशक्तीकरण और भारत को कौशल राजधानी बनाना’ (PM-SETU: Empowering Youth, Positioning India as Skill Capital) में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के महानिदेशक (प्रशिक्षण) दिलीप कुमार ने विश्लेषण किया है कि कैसे व्यावसायिक शिक्षा (vocational education) और कौशल प्रशिक्षण भारत के कार्यबल विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गए हैं।

लेखक रेखांकित करते हैं कि सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, एयरोस्पेस, रक्षा उत्पादन और इंडस्ट्री 4.0 जैसी रणनीतिक तकनीकों में भारी निवेश से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। साथ ही, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में वृद्ध होती आबादी के कारण वैश्विक स्तर पर कुशल मानव संसाधनों की मांग बढ़ रही है। अपनी युवा आबादी और जनसांख्यिकी लाभांश के साथ भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए, बल्कि दुनिया की ‘कौशल राजधानी’ (Skill Capital) बनने के लिए पूरी तरह तैयार है।

2. PM-SETU योजना: बड़े पैमाने पर संस्थागत सुधार

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) की संरचनात्मक चुनौतियों और उद्योग की बदलती जरूरतों के बीच के अंतर को पाटने के लिए ‘प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs’ (PM-SETU) योजना शुरू की गई है।

- योजना का पैमाना:** इस योजना के तहत 1,000 सरकारी ITI (जिनमें 200 Hub ITIs और 800 Spoke ITIs शामिल हैं) का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
- वित्तीय परिव्यय:** 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹60,000 करोड़ का विशाल निवेश किया गया है।
- उत्कृष्टता केंद्र:** राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTIs) के विकास के माध्यम से 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centres of Excellence - NCE) स्थापित किए जा रहे हैं।

3. शासन मॉडल: विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) और उद्योग भागीदारी

- SPV फ्रेमवर्क:** PM-SETU की सबसे अनूठी विशेषता इसका नया शासन मॉडल है, जिसके तहत प्रत्येक Hub ITI और उसके Spoke ITIs एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle - SPV) के तहत संचालित होंगे।

- **एंकर उद्योग भागीदार (Anchor Industry Partner):** इस SPV में एक एंकर उद्योग भागीदार की बहुसंख्यक हिस्सेदारी होगी और वह दिन-प्रतिदिन के अकादमिक और परिचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें सार्वजनिक जवाबदेही सुरक्षित रखेंगी।
- **स्थानीय कौशल मांग:** यह मॉडल पाठ्यक्रम योजना और संकाय विकास में सीधे उद्योग की भागीदारी सुनिश्चित करता है, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण मिल सके।

4. NEP 2020 के साथ एकीकरण और शिक्षण परिणाम

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन:** Hub ITI उद्योग की मांग के अनुसार मौजूदा ट्रेडों का आधुनिकीकरण करते हुए लगभग 4 नए ट्रेड पेश करेंगे। प्रशिक्षण को राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit

Framework) के तहत मॉड्यूलर लर्निंग ब्लॉक में व्यवस्थित किया जाएगा।

- **क्रेडिट संचय और गतिशीलता:** शिक्षार्थी (learners) क्रेडिट जमा कर सकते हैं और उच्च योग्यताओं तथा आजीवन सीखने के लिए लचीले रास्ते अपना सकते हैं।
- **शिक्षता (Apprenticeship) और प्लेसमेंट:** कक्षा की शिक्षा से आगे बढ़कर ऑन-द-जोब ट्रेनिंग, प्लेसमेंट समर्थन और करियर परामर्श को मजबूत किया गया है।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: PM-SETU के आयाम, संरचना और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका PM-SETU योजना के प्रमुख घटकों, शासन मॉडल और विकासात्मक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

PM-SETU आयाम	मुख्य फोकस व घटक	परिचालन पैमाना व निवेश	रणनीतिक व आर्थिक प्रभाव
ITI आधुनिकीकरण	1,000 सरकारी ITIs का उन्नयन (200 Hub और 800 Spoke ITIs).	5-वर्षीय अवधि में ₹60,000 करोड़ का बड़ा वित्तीय निवेश.	देश भर में व्यावसायिक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण.
शासन मॉडल (SPV)	विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) और एंकर उद्योग भागीदार की प्रबंधन भागीदारी.	प्रत्येक Hub-Spoke क्लस्टर में उद्योग-नेतृत्व वाला दैनिक संचालन.	पाठ्यक्रमों को उद्योग की वास्तविक और उभरती जरूरतों के अनुकूल बनाना.
उत्कृष्टता केंद्र (NCE)	5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centres of Excellence) की स्थापना.	प्रशिक्षक क्षमता निर्माण और उन्नत कौशल प्रशिक्षण.	वैश्विक मानकों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करना.
NEP 2020 एकीकरण	राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ मॉड्यूलर लर्निंग और क्रेडिट संचय.	शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा और कौशल के बीच लचीले मार्ग [cite: 106, 107].	बेहतर रोजगार क्षमता, शिक्षता (apprenticeship) और आजीवन सीखने का अवसर.

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख कौशल विकास, मानव संसाधन और संस्थागत सुधार के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (मानव संसाधन, कौशल विकास, शिक्षा नीतियां और आर्थिक विकास — रोजगार सृजन)

- **PM-SETU और संस्थागत सुधार:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे PM-SETU योजना (₹60,000 करोड़ निवेश और 1,000 ITIs का उन्नयन) पारंपरिक व्यावसायिक शिक्षा को आधुनिक औद्योगिक मांगों के अनुरूप ढाल रही है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और शासन:** विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) मॉडल के माध्यम से एंकर उद्योग भागीदारों को शामिल करने की प्रशासनिक नवीनता को रेखांकित करता है, जो सार्वजनिक जवाबदेही बनाए रखते हुए अकादमिक और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करता है।
- **जनसांख्यिकी लाभांश और वैश्विक कौशल राजधानी:** भारत की युवा आबादी को वैश्विक कार्यबल गतिशीलता और घरेलू विनिर्माण (Make in India) के लिए तैयार करने में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र की भूमिका को स्पष्ट करता है।

मुख्य परीक्षा कौशल विकास दृष्टिकोण: “जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ध्यान ऐसे संस्थानों के निर्माण पर रहा है जो कुशल, उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित हों। PM-SETU इस विकसित शासन दृष्टिकोण को दर्शाता है।” — दिलीप कुमार

विषय 8: डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन: नागरिक-केंद्रित परिवर्तन को गति देना (DIGITAL INDIA CORPORATION: DRIVING CITIZEN-CENTRIC TRANSFORMATION)

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC), MeitY, किसान सारथी 2.0, शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र (DIKSHA, ABC, APAAR ID, ब्लॉकचेन क्रेडेंशियल्स, विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना), आजीविका और सामाजिक सशक्तीकरण (LokOS, Poshan Tracker, NCW महिला हेल्पलाइन, MANAS, MY Bharat) (लेखक: अखिल कुमार, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, DIC)

डिजिटल इंडिया विजन: “डिजिटल इंडिया एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है। डिजिटल प्लेटफॉर्म समावेशन, पारदर्शिता और जीवन को आसान बनाने (Ease of Living) के साधन के रूप में कार्य करते हैं।” — नरेंद्र मोदी

1. कार्यकारी सारांश एवं डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की भूमिका

अगस्त 2026 के <योजना> अंक के छठे आलेख <डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन: नागरिक-केंद्रित परिवर्तन को गति देना> (Digital India Corporation: Driving Citizen-Centric Transformation) में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के प्रबंध निदेशक और सीईओ अखिल कुमार ने विश्लेषण किया है कि कैसे प्रौद्योगिकी ने नागरिकों और सरकार के बीच के रिश्ते को पारदर्शी, जवाबदेह और उत्तरदायी बनाया है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में, DIC विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक संस्थानों के लिए एक रणनीतिक प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है। यह शिक्षा, कृषि, महिला कल्याण, ग्रामीण आजीविका और युवाओं के जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म और उभरती तकनीकी समाधानों को विकसित और तैनात करता है।

2. शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांतिकारी बदलाव

- **DIKSHA प्लेटफॉर्म:** एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से बहुभाषी शिक्षण संसाधन, डिजिटल पाठ्यपुस्तकें और शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ABC):** यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की यह पहल छात्रों को APAAR ID के माध्यम से अकादमिक क्रेडिट को सुरक्षित रूप से संग्रहीत, स्थानांतरित और भुनाने की अनुमति देती है (NEP 2020 के तहत Multiple Entry-Multiple Exit)।
- **ब्लॉकचेन-संचालित क्रेडेंशियल्स:** अकादमिक रिकॉर्ड के छेड़छाड़-मुक्त (tamper-proof) जारी करने और सत्यापन के लिए Hyperledger तकनीक पर आधारित संप्रभु ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म।
- **विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना:** MeitY के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में उन्नत अनुसंधान और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।

3. आजीविका और सामाजिक समावेशन में डिजिटल भूमिका

- **किसान सारथी 2.0:** किसानों को समय पर AI-सक्षम और बहुभाषी कृषि सलाह प्रदान करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म (295+ लाख किसान लाभान्वित, 3.85+ लाख गांव कवर)।

- **LokOS प्लेटफॉर्म:** ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत स्व-सहायता समूह (SHG) सदस्यों, लखपति दीदी पहचान और आजीविका डेटा रिकॉर्डिंग के लिए सबसे बड़े grassroots डिजिटल प्लेटफॉर्मों में से एक।
- **इंडिया हैंडमेड प्लेटफॉर्म:** कपड़ा मंत्रालय की पहल, जो दूरदराज के कारीगरों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ती है और बिचौलियों को हटाती है।

4. सामाजिक कल्याण और नागरिक सहायता डिजिटल प्लेटफॉर्म

- **पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker):** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत पोषण सेवा वितरण की वास्तविक समय (real-time) निगरानी और बेहतर लक्ष्य निर्धारण।
- **NCW महिला हेल्पलाइन:** राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए शिकायत पंजीकरण, परामर्श और सहायता प्रदान करने वाला सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म।
- **MANAS:** नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के तहत नागरिकों को ड्रग्स से जुड़े अपराधों को सुरक्षित रूप से रिपोर्ट करने का चैनल।
- **MY Bharat:** युवाओं को राष्ट्र-निर्माण, स्वयंसेवा और अनुभवात्मक सीखने के अवसरों से जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म (2.21+ करोड़ युवा पंजीकृत)।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: DIC के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सामाजिक प्रभाव

नीचे दी गई तालिका डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) द्वारा संचालित प्रमुख डिजिटल पहलों, उनके उद्देश्यों और सामाजिक प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

डिजिटल डोमेन	प्रमुख प्लेटफॉर्म / पहल	मंत्रालय / सहयोगी संस्था	नागरिक सशक्तीकरण और प्रभाव
शिक्षा और अनुसंधान	DIKSHA, ABC (APAAR ID), ब्लॉकचेन क्रेडेंशियल्स, विश्वेश्वरैया पीएचडी	शिक्षा मंत्रालय / MeitY	समावेशी डिजिटल शिक्षा, क्रेडिट गतिशीलता और शोध को बढ़ावा
कृषि और आजीविका	किसान सारथी 2.0, LokOS, इंडिया हैंडमेड	ICAR / ग्रामीण विकास / कपड़ा मंत्रालय	किसानों को AI सलाह, SHG डिजिटलीकरण और कारीगरों को बाजार पहुंच
महिला एवं बाल कल्याण	पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker), NCW महिला हेल्पलाइन	MWCD / राष्ट्रीय महिला आयोग	वास्तविक समय पोषण निगरानी और महिलाओं के लिए तुरंत सहायता
युवा और सुरक्षा	MY Bharat, MANAS (नारकोटिक्स नियंत्रण)	युवा मामले और खेल मंत्रालय / NCB	युवा स्वयंसेवा, राष्ट्र-निर्माण और ड्रग अपराधों की सुरक्षित रिपोर्टिंग

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख ई-गवर्नेंस, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (ई-गवर्नेंस — अनुप्रयोग, सफलताएं, सीमाएं और साइबर सुरक्षा; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी — डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा)

- डिजिटल इंडिया और नागरिक-केंद्रित शासन: यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) शिक्षा (DIKSHA,

ABC), कृषि (किसान सारथी), और कल्याण (पोषण ट्रैकर) जैसे क्षेत्रों में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शासन को पारदर्शी, जवाबदेह और सुलभ बना रहा है।

- डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI): संप्रभु ब्लॉकचेन क्रेडेंशियल्स, LokOS और MY Bharat जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से शासन में प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और समावेशी उपयोग को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा डिजिटल इंडिया दृष्टिकोण: “डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक संस्थानों को ऐसे डिजिटल समाधान बनाने में सहायता करके एक सक्षम भूमिका निभाई है जो शिक्षार्थियों, किसानों, महिलाओं, युवाओं, कारीगरों, शोधकर्ताओं और नागरिकों को समान रूप से सशक्त बनाते हैं।” — अखिल कुमार

विषय 9: भविष्य को रोशन करना: भारत की ऊर्जा दक्षता क्रांति (LIGHTING THE FUTURE: INDIA'S ENERGY EFFICIENCY REVOLUTION)

ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा तीव्रता (Energy Intensity) में गिरावट, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना, UJALA कार्यक्रम (36 करोड़+ LED बल्ब), स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम, मानक एवं लेबलिंग (Standards & Labelling), और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (लेखक: धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, विद्युत मंत्रालय एवं करमजीत कौर, IES)

ऊर्जा दक्षता विजन: “ऊर्जा दक्षता सबसे सस्ती, सबसे स्वच्छ और सबसे सुरक्षित ऊर्जा है—वह ऊर्जा है जिसे कभी उत्पादित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भारत की ऊर्जा तीव्रता में गिरावट वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ में से एक है।” — धीरज कुमार श्रीवास्तव एवं करमजीत कौर

1. कार्यकारी सारांश एवं ऊर्जा दक्षता का रणनीतिक महत्व

अगस्त 2026 के 'योजना' अंक के दसवें आलेख 'भविष्य को रोशन करना: भारत की ऊर्जा दक्षता क्रांति' (Lighting The Future: India's Energy Efficiency Revolution) में विद्युत मंत्रालय के मुख्य अभियंता धीरज कुमार श्रीवास्तव और IES अधिकारी करमजीत कौर ने विश्लेषण किया है कि कैसे पिछले एक दशक में भारत की ऊर्जा संरक्षण और दक्षता नीतियों ने देश के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति दी है।

लेखक रेखांकित करते हैं कि विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ते हुए, तीव्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रिक गतिशीलता के कारण ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ेगी। इस मांग को पूरा करने के लिए केवल ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। MOSPI की 'एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025' के अनुसार, भारत की ऊर्जा तीव्रता (प्रति यूनिट GDP ऊर्जा खपत) में उल्लेखनीय गिरावट आई है और ऊर्जा दक्षता सुधार दर वैश्विक तुलना में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।

2. प्रमुख ऊर्जा दक्षता पहलें और कार्यक्रम

- PAT (Perform, Achieve and Trade) योजना:** थर्मल पावर, सीमेंट, स्टील, एल्यूमीनियम और उर्वरक जैसे ऊर्जा-सघन उद्योगों के लिए बाजार आधारित योजना, जिसके तहत 1,300 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है। इससे 23 मिलियन टन तेल समतुल्य

(MTOE) की ऊर्जा बचत और 110 मिलियन टन से अधिक CO₂ उत्सर्जन टला है।

- UJALA कार्यक्रम:** EESL द्वारा संचालित यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर-subsidy LED वितरण कार्यक्रम है, जिसके तहत 36 करोड़ से अधिक LED बल्ब वितरित किए गए हैं, जिससे प्रतिवर्ष 48 अरब यूनिट बिजली और ₹19,000 करोड़ से अधिक की वित्तीय बचत होती है।
- स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP):** शहरी और ग्रामीण भारत में पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को LED प्रणालियों से बदलना, जिससे नगर पालिकाओं को प्रतिवर्ष ₹6,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई है।

3. भवन निर्माण, मानक एवं लेबलिंग, और परिवहन क्षेत्र

- ऊर्जा संरक्षण और संधारणीय भवन कोड (ECBC):** वाणिज्यिक और आवासीय संरचनाओं में 25% से 50% तक ऊर्जा खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- मानक और लेबलिंग (Standards & Labelling):** वर्तमान में 40 उपकरण श्रेणियों को कवर करते हुए उपभोक्ताओं को ऊर्जा-कुशल उत्पाद चुनने के लिए सशक्त करना।
- CAFE मानदंड:** 2017 से लागू कॉर्पोरेट औसत ईंधन अर्थव्यवस्था (CAFE) मानदंडों के माध्यम से यात्री कार खंड में ईंधन दक्षता में सुधार।
- संचयी ऊर्जा बचत:** आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वार्षिक ऊर्जा बचत 2014-15 के ~3 MTOE से बढ़कर 2024-25 में ~65 MTOE हो गई है, जिससे ऊर्जा दक्षता भारत का सबसे बड़ा 'वर्चुअल पावर प्लांट' बन गई है।

4. भविष्य की दिशा: ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और कार्बन बाजार

- ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022:** दक्षता और उत्सर्जन में कमी के लिए नए बाजार प्रोत्साहन और नियामक ढांचे की स्थापना।
- कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS):** भारत के घरेलू कार्बन बाजार को स्थापित करना, जो उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा दक्षता अपनाने के लिए आर्थिक रूप से पुरस्कृत करेगा।

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: ऊर्जा दक्षता पहल, पैमाना और प्रभाव

नीचे दी गई तालिका प्रमुख ऊर्जा दक्षता पहलों, उनके परिचालन पैमाने और राष्ट्रीय प्रभावों का विवरण प्रस्तुत करती है:

डिजिटल डोमेन	प्रमुख प्लेटफॉर्म / पहल	मंत्रालय / सहयोगी संस्था	नागरिक सशक्तीकरण और प्रभाव
शिक्षा और अनुसंधान	DIKSHA, ABC (APAAR ID), ब्लॉकचेन क्रेडेंशियल्स, विश्वेश्वरैया पीएचडी	शिक्षा मंत्रालय / MeitY	समावेशी डिजिटल शिक्षा, क्रेडिट गतिशीलता और शोध को बढ़ावा
कृषि और आजीविका	किसान सारथी 2.0, LokOS, इंडिया हैंडमेड	ICAR / ग्रामीण विकास / कपड़ा मंत्रालय	किसानों को AI सलाह, SHG डिजिटलीकरण और कारीगरों को बाजार पहुंच
महिला एवं बाल कल्याण	पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker), NCW महिला हेल्पलाइन	MWCD / राष्ट्रीय महिला आयोग	वास्तविक समय पोषण निगरानी और महिलाओं के लिए तुरंत सहायता
युवा और सुरक्षा	MY Bharat, MANAS (नारकोटिक्स नियंत्रण)	युवा मामले और खेल मंत्रालय / NCB	युवा स्वयंसेवा, राष्ट्र-निर्माण और ड्रग अपराधों की सुरक्षित रिपोर्टिंग

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र III (पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और संधारणीय विकास)

- **ऊर्जा दक्षता और जलवायु कार्यवाही:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारत ने PAT, UJALA और ऊर्जा तीव्रता में गिरावट (प्रति वर्ष ~65 MTOE बचत) के माध्यम से बिना विकास आकांक्षाओं से समझौता किए अपने पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले हासिल किया है।
- **बाजार आधारित जलवायु तंत्र:** ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के माध्यम से हरित अर्थव्यवस्था को संस्थागत रूप देने के प्रयासों को रेखांकित करता है।

मुख्य परीक्षा ऊर्जा दक्षता दृष्टिकोण: “ऊर्जा दक्षता सबसे सस्ती, सबसे स्वच्छ और सबसे सुरक्षित ऊर्जा है—वह ऊर्जा है जिसे कभी उत्पादित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भारत की ऊर्जा तीव्रता में गिरावट वैश्विक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ में से एक है।” — धीरज कुमार श्रीवास्तव एवं करमजीत कौर

विषय 10: पहुंच से परे: डिजिटल युग में सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षित करना (BEYOND ACCESS: SECURING SOCIAL SECURITY IN THE DIGITAL AGE)

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI), JAM ट्रिनिटी, साइबर धोखाधड़ी और छाया अर्थव्यवस्था (Jamtara, Nuh, डिजिटल अरेस्ट), मूल अकाउंट्स, और समावेशन व सुरक्षा के बीच संतुलन (लेखक: संदीप कुमार शुक्ल, प्रोफेसर एवं निदेशक, IIIT हैदराबाद)

सामाजिक सुरक्षा विजन: “वित्तीय समावेशन, कल्याणकारी वितरण और सामाजिक सुरक्षा अंततः प्रौद्योगिकी परियोजनाएं नहीं हैं; वे विश्वास परियोजनाएं हैं। प्रौद्योगिकी ने भारत को पाइपलाइन दी है। क्या इसके माध्यम से सशक्तिकरण बढ़ता है या शोषण, यह मानव संस्थानों, कानूनों और साक्षरता पर निर्भर करता है।” — संदीप कुमार शुक्ल

1. कार्यकारी सारांश एवं डिजिटल भारत का बुनियादी ढांचा

अगस्त 2026 के ‘योजना’ अंक के आठवें आलेख ‘पहुंच से परे: डिजिटल युग में सामाजिक सुरक्षा को सुरक्षित करना’ (Beyond Access: Securing Social Security in the Digital Age) में IIIT हैदराबाद के प्रोफेसर और निदेशक संदीप कुमार शुक्ल ने विश्लेषण किया है कि कैसे भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (DPI) ने वित्तीय समावेशन और कल्याणकारी वितरण को बदल दिया है। साथ ही, यह आलेख उन गंभीर सुरक्षा चुनौतियों और साइबर धोखाधड़ी को उजागर करता है जो डिजिटल रूप से कम साक्षर नागरिकों को प्रभावित कर रही हैं।

लेखक रेखांकित करते हैं कि आधार के माध्यम से एक अरब से अधिक लोगों को डिजिटल पहचान मिली है, और UPI ने डिजिटल भुगतान को लोकतांत्रिक बनाया

है। हालांकि, इस व्यापक समावेशन के पीछे एक ‘छाया अर्थव्यवस्था’ (shadow economy) भी पनप रही है जो नए उपयोगकर्ताओं की कमजोरियों का फायदा उठाती है।

2. डिजिटल इंडिया और वित्तीय समावेशन की वास्तुकला

- **आधार और इंडिया स्टैक:** एक अरब से अधिक सत्यापित डिजिटल पहचान , DigiLocker के माध्यम से पेपरलेस शासन , और वीडियो/ऑडियो e-KYC.
- **UPI का विस्तार:** सड़क विक्रेताओं से लेकर बड़े खुदरा विक्रेताओं तक त्वरित, इंटरऑपरेबल और लगभग मुफ्त भुगतान , तथा RBI द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (e-Rupee) की शुरुआत.
- **JAM ट्रिनिटी और कल्याणकारी वितरण:** जन धन खाते, आधार और मोबाइल के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) , जिससे बिचौलियों और लीकेज को समाप्त किया गया है.

3. साइबर धोखाधड़ी और छाया अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

- **संगठित साइबर अपराध के केंद्र:** झारखंड का जामताड़ा, हरियाणा का नूह, और राजस्थान का भरतपुर फ़िशिंग, सेक्सटोरशन, और फर्जी कस्टमर-केयर घोटालों के हब बन चुके हैं। नवीनतम खतरा ‘डिजिटल अरेस्ट’ (वीडियो कॉल पर पुलिस या कानून प्रवर्तन अधिकारी बनकर डराना) है.
- **भेद्यता की विषमता (Asymmetry of Vulnerability):** अपराधी डिजिटल रूप से अत्यधिक कुशल हैं, जबकि नए उपयोगकर्ता (पेंशनभोगी, किसान, दिहाड़ी मजदूर) आसानी से स्फूट सदेशों के झांसे में आ जाते हैं और अपने जीवन भर की बचत खो बैठते हैं। जन धन खातों का ‘मूल अकाउंट्स’ (mule accounts) के रूप में दुरुपयोग एक गंभीर चिंता है.
- **संस्थागत और कानूनी अंतराल:** यद्यपि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDPA) 2023 पारित किया गया है और 14C (Indian Cyber Crime Coordination Centre) सक्रिय है, फिर भी साइबर अपराधों में सजा का प्रतिशत अभी भी 5% से कम है.

4. समावेश और सुरक्षा के बीच संतुलन (Pillars of Action)

समावेशी डिजिटलीकरण को सुरक्षित बनाने के लिए निम्नलिखित कदम आवश्यक हैं:

- **मानव-सहायता प्राप्त चैनल:** कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) और बैंकिंग संवाददाताओं को केवल संक्रमणकालीन अवशेष न मानकर लेखा परीक्षा ट्रेल्स और प्रशिक्षण के साथ मजबूत करना.
- **रेलिंग में सुरक्षा (Security in Rails):** वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी, असामान्य हस्तांतरण पर कूलिंग पीरियड, और धोखाधड़ी वाले भुगतानों को तुरंत फ्रीज व रिवर्स करने के तंत्र.
- **डिजिटल और वित्तीय साक्षरता:** स्थानीय भाषाओं और विश्वसनीय सामुदायिक चैनलों के माध्यम से व्यापक साक्षरता अभियान चलाना.

5. विश्लेषणात्मक तुलनात्मक मैट्रिक्स: डिजिटल वास्तुकला, साइबर जोखिम और रणनीतिक समाधान

नीचे दी गई तालिका डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, साइबर धोखाधड़ी के जोखिमों और भविष्य के रणनीतिक समाधानों का विवरण प्रस्तुत करती है:

सुरक्षा आयाम	मुख्य डिजिटल वास्तुकला	प्रमुख चुनौतियां व जोखिम	रणनीतिक समाधान व सुधार
डिजिटल पहचान व भुगतान	आधार, इंडिया स्टैक, DigiLocker और UPI.	कम साक्षर उपयोगकर्ताओं द्वारा बिचौलियों पर अत्यधिक निर्भरता.	मानव-सहायता प्राप्त CSC चैनलों और मजबूत डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा.
कल्याणकारी वितरण	JAM ट्रिनिटी, PFMS और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT).	लीकेज और बिचौलियों की समाप्ति के बावजूद सुरक्षा अंतराल.	सक्रिय लाभार्थी पहचान और मजबूत डेटा संरक्षण कानून लागू करना.
छाया अर्थव्यवस्था व धोखाधड़ी	जामताड़ा, नूह, सेक्सटोरशन और 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाले.	म्यूल अकाउंट्स का दुरुपयोग और पीड़ितों की बचत का नुकसान.	रियल-टाइम लेनदेन निगरानी और त्वरित फंड प्रीजिंग तंत्र.
विश्वास और संस्थाएं	कानूनी ढांचा (DPDPA 2023) और 14C साइबर समन्वय.	कम सजा दर (<5%) और तकनीकी रूप से सीमित पुलिस क्षमताएं.	प्रभावी जांच क्षमता, त्वरित न्याय और जवाबदेह बिचौलिये.

6. सिविल सेवा परीक्षा (UPSC / State PCS) मुख्य परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण

सिविल सेवा परीक्षा के विभिन्न प्रश्न-पत्रों के लिए यह आलेख साइबर सुरक्षा, ई-गवर्नेंस और आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है: सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र II & III (ई-गवर्नेंस के अनुप्रयोग, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, और आंतरिक सुरक्षा — साइबर अपराध और साक्षरता)

- **डिजिटल समावेशन और साइबर सुरक्षा:** यह आलेख विश्लेषण करता है कि कैसे भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (आधार, UPI, JAM) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, लेकिन साथ ही नए साइबर खतरों (जामताड़ा, डिजिटल अरेस्ट) ने सामाजिक सुरक्षा के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी की हैं.

- **विश्वास परियोजना के रूप में प्रौद्योगिकी:** वित्तीय समावेशन को केवल तकनीकी परियोजना न मानकर एक 'विश्वास परियोजना' (trust project) के रूप में देखने की आवश्यकता है, जिसमें मानव संस्थान, मजबूत कानून, त्वरित जांच और डिजिटल साक्षरता शामिल हों.

मुख्य परीक्षा सामाजिक सुरक्षा दृष्टिकोण: “वित्तीय समावेशन, कल्याणकारी वितरण और सामाजिक सुरक्षा अंततः प्रौद्योगिकी परियोजनाएं नहीं हैं; वे विश्वास परियोजनाएं हैं। प्रौद्योगिकी ने भारत को पाइपलाइन दी है। क्या इसके माध्यम से सशक्तीकरण बढ़ता है या शोषण, यह मानव संस्थानों, कानूनों और साक्षरता पर निर्भर करता है।” — संदीप कुमार शुक्ल